उपसभापति महोदय, रेलवे में सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा, आजकल दोनों भगवान भरोसे हैं। रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। ओडिशा के ट्रेन हादसे में मारे गए सैकड़ों यात्रियों के परिवारों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं, क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। यात्रियों की सुरक्षा की सुध भला कौन ही ले, जब मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है! 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मूंगावली स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वन्दे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना-लखनऊ-इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट कराकर आप ट्विटर पर डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाट जोह रहे इस देश के पास लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ-पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती, मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Imran Pratapgarhi: Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Demand to start Railway services from Baripada to Balasore in Odisha

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, किसी भी अंचल का विकास तभी संभव है, जब उस अंचल में यातायात की संपूर्ण सुविधा हो और देश के किसी भी स्थान से उस अंचल में सुविधा के साथ पहुँचा जा सके, चाहे वह विमान सेवा हो, रेल सेवा हो, बस सेवा हो या कोई भी सेवा हो। ओडिशा के मयूरभंज जिले में कप्तिपाड़ा सब डिवीजन है, जहां के लोग रेल सेवा पाने से वंचित हैं। भारत को स्वाधीन हुए 75 साल हो गए, लेकिन दुख की बात यह है कि इस जिले के कप्तिपाड़ा सब-डिवीज़न के लाखों लोग रेल सेवा से वंचित हैं। इस इलाके के लोग रेल सेवा पाने के लिए सौ किलोमीटर दूर यातायात करते हैं। मेरा रेल विभाग से प्रस्ताव और अनुरोध है कि बारीपदा से खुन्टा, उदला, कप्तिपाड़ा, नीलगिरी होकर बालेश्वर स्टेशन तक रेल कनेक्ट की जाए। वहां रेल कनेक्ट होगी तो उस इलाके के लोग रेल सेवा पा सकेंगे और भुवनेश्वर-दिल्ली के जैसे देश की अन्य सभी जगहों पर सुविधापूर्वक यातायात कर सकेंगे। अगर इस अंचल में रेल सेवा होगी तो इसका विकास भी होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Mamata Mohanta: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Demand for homes to the poor of Odisha under Pradhan Mantri Awas Yojana

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, the Centre launched the Pradhan Mantri Awas Yojana with the very laudable objective of 'housing for all' to provide pucca houses with basic amenities to the homeless or those living in dilapidated kuchcha structures. Under this Yojana, the Odisha Government proposed housing assistance to be covered under the PMAY for 15 lakh houses. This included houses to be provided to a large population of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes and also to the people who were affected by Fani Cyclone.

In December, 2021, the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, wrote a letter to the hon. Prime Minister seeking more houses for Fani cyclone-hit families and also the poor in the tribal and backward districts of the State. But, unfortunately, after three-and-a-half years, despite persuasion by all the Members of Parliament of Biju Janata Dal in both the Houses and also submitting a memorandum to the concerned Minister, only 8 lakh houses have been sanctioned and still 7 lakh houses have been left behind. The result is that there is a large chunk of people in these tribal areas who have not been able to get houses even now.

In order to support those deprived of their right to shelter, the Government of Odisha, under the leadership of the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has come out with *Mo Ghara* Scheme, that is, My House Scheme, in 2023. It is a credit-linked subsidy scheme. This was done because there was a large chunk of people who could not be covered under the Central scheme. Under this scheme, loans up to Rs.3 lakhs are being provided, and the more significant thing is that persons with disabilities are being covered, who were not being covered under the Pradhan Mantri Awas Yojana. The financial implication of this Mo Ghara Scheme is that in two years, Rs.2,150 crores are proposed to be met from the State Budget.

Now, Sir, through you, I would like to urge upon the Government that remaining 7 lakh houses, which have not been provided by the Central Government, could be provided to those people in Odisha who have been deprived of this. This would actually ensure that the people, who are actually in the lower strata of society in